सुविचार

दूसरो के लिए तो काम हर कोई कर लेता हैं, जो कर दे खुद का काम खड़ा, ऐसा कोई-कोई ही कर पाता हैं।

साप्ताहिक

युवा प्रदेश

Freedom Of Speech

RNI. NO. MPHIN/2015/76299

संपादक-नागेश नरवरिया

वर्ष 7, अंक-42 www.yuvapradesh.in भोपाल, शुक्रवार 25 नवंबर 2022 ypnews24@gmail.com पृष्ठ -8 मूल्य 2 रुपये

Mother's Basket
Kitchen Herbs & Spices
Swad jo pahuche dil tak

भारत में किस प्रकार की उपाधिया मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा जानिए/Fundamental of Right......

अक्सर हम प्राचीन काल, मध्यकाल, और ब्रिटिश शासन में सुना करते थे कि राय बहादुर, राय साहब, राजा साहब,महाराजा साहब, लार्ड साहब पधार रहे हैं या आगमन हो रहा है ऐसे ही उपनाम को हम उपाधियां कहते हैं जिससे निम्न वर्ग के लोग पृथक होते थे एवं भारतीय संविधान में सभी को अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक भारत के हर नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है एवं सभी नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे इसलिए संविधान में उपाधियों का अंत किया गया है जानिए।

लेखक एडवोकेट बीआर अहिरवार(विधिक सलाहकार एवं पत्रकार एवं होशंगाबाद) 9827737665

भारतीय संविधान अधिनियम,1950 का अनुच्छेद 18 की परिभाषा?

राज्य के किसी भी व्यक्ति को चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान करने से मना करता है लेकिन इसके निम्न नियम एवं अपवाद भी है जानिए-

1. राज्य सेना एवं शिक्षा संबंधित प्रदर्शन में उपाधि प्रदान कर सकता है।
2. कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
3. राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नागरिक या विदेशी नागरिक भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि, पद, भेंट या कोई उपलब्धि स्वीकार नहीं कर सकता है।

अपवाद-

शैक्षणिक उपाधियां जैसे कि बीए, एमए, पीएचडी, एमबीबीएस, बीई, एमबीए, एलएलबी आदि अनुच्छेद 18 की परिधि में नहीं आते हैं। सेना में विशिष्ट शौर्य का प्रदर्शन एवं शिक्षा, समाज-विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, कला आदि जैसे भारत रत्न पुरस्कार, पद्द विभूषण - भूषण पुरुस्कार,पद्द श्री पुरुस्कार, परम वीर चक्र , वीर चक्र , महावीर चक्र आदि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है।

हिंदी में श्रेष्ठ विधि लेखन के दिये जाने वाला पुरस्कार जैसे विधि एवं न्यायालय मंत्रालय भारत सरकार का राज पुरुस्कार, गृह मंत्रालय भारत सरकार का पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरुस्कार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अखिल भारतीय वानिकी साहित्य पुरुस्कार, भाषा के क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा दिये जाने वाला पुरुस्कार डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा पुरुस्कार, मध्यप्रदेश सरकार का डॉ भीमराव राव अम्बेडकर पुरुस्कार आदि पुरुस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है।

विशेष नोट- संविधान का अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार के दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह अनुच्छेद केवल निदेशात्मक हैं, आदेशात्मक नहीं लेकिन संसद को विधि बनाकर इसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान करने की पूरी शक्ति प्राप्त है लेकिन संसद द्वारा अभी तक कोई दंडात्मक विधि नहीं बनाई गई है।

मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्रों के उद्योग और निवेश के लिए पर्याप्त संभावनाएँ : मुख्यमंत्री

❑ भोपाल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है। मध्यप्रदेश, पावर सरप्लस राज्य है, दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी मध्यप्रदेश के सोलर प्लांट से चल रही है। प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। स्किल्ड मेन पावर के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, प्रदेश के लोग शांति से कार्य करने में विश्वास रखते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी प्रो-एक्टिव है। यह सब बिन्दु औद्योगिक विकास और निवेश के लिए हमारी ताकत है। राज्य सरकार उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार अपनी विभिन्न नीतियों में जरूरी बदलाव करने के लिए सहमत है। प्रदेश में सभी क्षेत्रों के उद्योग और निवेश के लिए पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। उद्योगपति एंव निवेशक आएँ, बातचीत करें और उद्योग तथा प्रदेश की प्रगति में सहभागी बने। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैंगलुरू में ÷मध्यप्रदेश में निवेश अवसर÷ पर संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। बैंगलुरू के होटल ताज यशवंतपुर में संवाद सत्र में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

पर्याप्त लैंड बैंक-बिजली-पानी-रोड कनेक्टिविटी और बेहतर कानून-व्यवस्था प्रदेश की ताकत

श्री ओम प्रकाश सखलेचा, विभिन्न उद्योगपति और निवेशक सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निवेशकों से यह संवाद मात्र कर्मकांड नहीं है, अपितु प्रदेश के विकास की तड़प, जिद, जुनून और जज्बे से उत्पन्न भावना है जिसे व्यवहारिक रूप देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन्दौर में 11 और 12 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है। इससे पहले 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, जिसमें 80 से अधिक देशों में निवास कर रहे प्रवासी भारतीय सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्योगपतियों और निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

मध्यप्रदेश में लागू होने वाला है पेसा कानून क्या है जानिए/Legal advice....

आदिवासियों के संरक्षण में बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून हैं पेसा एक्ट,1996, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 15 अगस्त के अवसर पर आदिवासियों के हित में कहाँ गया है कि सम्पूर्ण प्रदेश में पेसा कानून पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा उससे पहले पेसा कानून को आदिवासी को समझाने के लिए जागरूक किया जा रहा है आइये हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं कि क्या है ये पेसा कानून।

पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,1996 अर्थात पेसा एक्ट,1996-?

73 वाँ भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम,1992 में पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई हैं, इसी संशोधन के नियम क्रमांक 02 में यह उपबंध हैं कि पंचायतों में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए संख्या के आधार पर आरक्षित कर लाभ दिया जाए। इसी अधारशीलता पर पेसा एक्ट पारित किया गया है, यह अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद 1996 में अस्तित्व में आया एवं 24 दिसम्बर 1996 को लागू किया गया इस अधिनियम में कुल पाँच धाराएं है ।

पेसा अधिनियम कहाँ-कहाँ लागू है जानिए-

संविधान की अनुसूचित पाँच में स्थित वो सभी अनुसूचित क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होगा वर्तमान में यह दस राज्यो में प्रभावी होगा- आंध्रप्रदेश,तेलगांना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, एवं राजस्थान जो अनुसूचित क्षेत्रों की श्रेणी

में आते हैं।

अधिनियम का उद्देश्य, महत्व क्या है-?

भारत में आदिवासी परम्परा, रीतिरिवाजों, संस्कृति आदि का संरक्षण करना एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में एक ग्राम समिति होगी उस समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा एवं ग्राम के महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम समिति द्वारा लिए जाएंगे जैसे कि ग्राम पंचायत में होने वाले विकास, अनुसूचित जनजाति समुदाय की भूमि का संरक्षण करना, ग्राम में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, बाजारों की देख रेख एवं ऋष्ठ वसूली आदि करना, बेरोजगारी के कारण गाँव छोड़कर पलायन करने वाले जनजाति समुदाय के व्यक्ति की जानकारी रखना आदि सभी अधिकार ग्राम सभा समिति के पास होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ग्राम सभा समिति ग्राम की समस्याओं को सीधे राज्य सरकार के समक्ष भेज सकती है एवं समस्या का निदान प्राप्त कर सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आदिवासी समुदाय के लोगों से ग्राम साहूकार बंधक मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों एवं उनकी प्रथाओं, रीति-रिवाजों का संरक्षण करना इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

-लेखक एडवोकेट बीआर अहिरवार(विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

मध्य प्रदेश परिसंघ संभागीय ने कहा, उपायुक्त जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग संभाग ग्वालियर के प्राचार्य को निलंबित किया जाए तथा सहायक आयुक्त के प्रभाव से तत्काल हटाया जाए

युवा प्रदेश ❑ ग्वालियर

मूलचंद मेधोनिया भोपाल

श्री एच बी शर्मा कार्यालय संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग ग्वालियर संभाग ग्वालियर से नियमों के विरुद्ध वेतन प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि यह सहायक संचालक नहीं है इनका मूल पद प्राचार्य है इनका स्थानांतरण शासन से कुछ वर्ष पूर्व संभागीय उपायुक्त के विकल्प पर हुआ है संभागीय उपायुक्त कार्यालय में इनकी उपस्थिति देने के बाद इन्हें तत्काल संभाग जनजाति कार्य विभाग के विद्यालय में रिक्त प्राचार्य के पद पर कार्यमुक्त किया जाना था जो आज तक नहीं किया गया है रिक्त पद के लिए कार्य मुक्त किया जाए इसलिए इनके साथ इनको कार्यमुक्त नहीं करने वाले भी दोषी हैं कार्रवाई की जाए 2 श्री एचबी शर्मा जनजाति कार्य विभाग के प्राचार्य हैं संभागीय उपायुक्त कार्यालय सहायक संचालक के पद पर शासन ने इनकी पदस्थापना नहीं की गई है सहायक संचालक के पद के विरुद्ध वेतन प्राप्त कर रहे हैं इनकी सर्विस बुक भी इसी कार्यालय में है इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है अथवा कोई प्रभार प्राप्त करना है तो इनके द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को आदेशों की कॉपी नहीं दिलाई जाती हैं।

इसमें इनके द्वारा भ्रष्टाचार अपनाया जाता है अपनी राजनीति की दम पर ए काम करते हैउदाहरण के लिए आदेश सलंगन है जिसमें श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग द्वारा दोषी पाए जाने पर इनकी वेतन वृद्धि रोकी गई और रोकी गई वेतन वृद्धि के आदेश को सर्विस बुक में इंद्राज कर प्रमाणित कॉपी संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा मांगी गई लेकिन इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई और रोकी गई वेतन वृद्धि कल आप भी प्राप्त कर लिया इसलिए इन को निलंबित किया जाए आदेश की कॉपी सलंगन है साथ ही आयुक्त महोदय के पत्र की कॉपी भी सलंगन है अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए निलंबित कर विभागीय जांच स्थापित की जाए 3

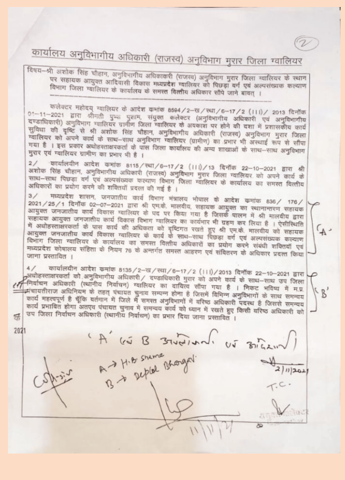

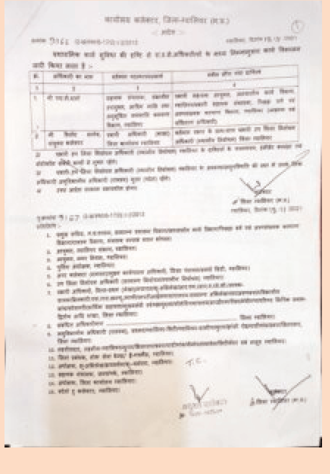

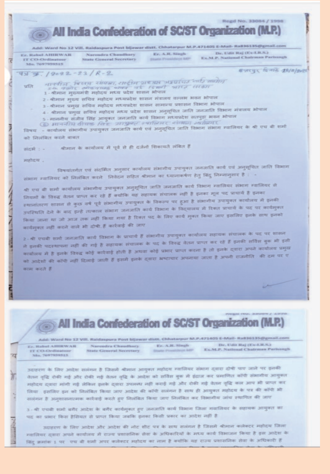

All India Confederation of SC/ST Organization (M.P.)

श्री एचबी शर्मा बगैर आदेश के बगैर कार्यमुक्त हुए जनजाति कार्य विभाग जिला गवालियर के सहायक आयुक्त का पद का प्रभार किस हैसियत से प्राप्त किया जबकि इनका किसी प्रकार का आदेश नहीं है इंजीनियर राहुल अहिरवार के लिए आदेश और आदेश की नोट शीट पत्र के साथ सलंगन है जिसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर द्वारा अपने कार्यालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया है इस आदेश के बिंदु क्रमांक 1 पर एच बी शर्मा अपर कलेक्टर महोदय का नाम है क्योंकि यह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं प्राचार्य जिनको सहायक आयुक्त जनजाति कार्य जिला गवालियर का प्रभार दिया है राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं है 4 आदेश के बिंदु क्रमांक 2 पर श्री विनोद भार्गव संयुक्त कलेक्टर का नाम है ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है श्री एच बी शर्मा जो जनजाति कार्य विभाग में सहायक आयुक्त का गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं प्रभार प्राप्त किया है यदि इस आदेश में इनका नाम होता तो इनके नाम के साथ इनका मूल पद का उल्लेख भी होता और इनका नाम इस आदेश के बिंदु क्रमांक 1 पर नहीं होता क्योंकि संयुक्त कलेक्टर विनोद भार्गव वरिष्ठ अधिकारी है साथ ही साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है आदेश के बिंदु क्रमांक 1 पर विनोद भार्गव जी का नाम होता क्योंकि धोखे में रखकर सहायक आयुक्त का कार्य कर रहे हैं यह तो प्राचार्य है आदेश में कभी भी कनिष्ठ का नाम ऊपर नहीं होता है इससे स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर महोदय का नाम है उन्होंने प्रशासन को गुमराह किया है इसलिए निलंबित किया जाए 5 श्री एचबी शर्मा ग्वालियर संभाग के संभागीय कार्यालय जनजाति कार्य विभाग संभागीय उपायुक्त कार्यालय संभाग ग्वालियर को किसी प्रकार की आदेश में कॉपी नहीं दी गई जो दिया जाना था 6 आदेश में इस बात का भी उल्लेख नहीं है की संभागीय उपायुक्त कार्यालय के कार्य के साथ-साथ सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला गवालियर का प्रभार सौंपा जाता है। श्री शर्मा को आज तक संभागीय उपायुक्त कार्यालय से कार्यमुक्त भी नहीं किया गया तो बगैर कार्य मुक्त हुए उन्होंने सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला गवालियर में कैसे ज्वाइन हुए धोके से प्रभाव प्राप्त कर लिया इन्हें अपने पद के बारे में अपनी पदस्थापना के बारे में आदेश मिलने के तुरंत बाद जिला प्रशासन को अवगत कराना था जो इनके द्वारा नहीं कराया गया इसलिए इन को निलंबित किया जाए 8 संभागीय उपायुक्त कार्यालय में इनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा तो इनको वेतन किस हैसियत से दिया जा रहा है संभागीय उपायुक्त कार्यालय के संभागीय उपायुक्त द्वारा वेतन की वसूली की जाए और श्री शर्मा को निलंबित कर विभागीय जांच स्थापित की जाये आदेश और नोटशीट से स्पष्ट है तीसरी बार कलेक्टर महोदय से सहायक आयुक्त का प्रभार के आर्डर करा ए हैं किस तरह के गलत गुमराह कर या धोखे में रखकर कराए जा रहे हैं श्री एच बी शर्मा सहित श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष नोटशीट और आर्डर प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए 9 संभागीय कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी अधिकारी को जिले में प्रभार देने के श्रीमान कलेक्टर महोदय को अधिकार नहीं है इसलिए सलंगन आदेश स्वतं गलत है आदेश के लिए प्रारूप और फाइल कलेक्टर साहब के पास भेजने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए राहुल अहिरवार ने शासन-प्रशासन मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि एचबी शर्मा प्राचार्य को उनके मूल पद पर पदस्थ करने के लिए विद्यालय में पद रिक्त हो वहां के लिए कार्य किया जाए इनकी सैकड़ों लंबित शिकायतों की निष्पक्ष जांच शासन आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में लंबित है और शासन में लंबित है एवं जनजाति कार्य विभाग जिला ग्वालियर में सहायक आयुक्त का गलत तरीके से बगैर आदेश के बगैर कार्यमुक्त हुए सहायक आयुक्त का कार्य कर रहे श्री एचवी शर्मा को निलंबित करके इनके कार्यकाल की संपूर्ण जांच करने की मांग संभागीय संयोजक आई टी मध्य प्रदेश परिसंघ इंजी राहुल अहिरवार ने की है ।

शहीद वीर मनीराम अहिरवार जी की 107 वीं जयंती कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा मनाई गई

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह को भोपाल अजा जिला अध्यक्ष श्री महेश नंदमेहर ने सौंपा वचन पत्र के लिए सुझाव एंव मांग पत्र सौंपा गया

युवा प्रदेश ❑भोपाल

देश की आजादी में हर वर्ग व धर्म के महापुरुषों ने अपना अपना योगदान और कुर्बानी देकर आजादी दी है। सन 19 42 के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के आवाहन पर चल रहे अंग्रेजों भारत छोड़ो के आन्दोलन में शामिल होने वाले चीचली गोंड महाराज श्री शंकर प्रताप सिंह जू देव जी के खास सेवादार वीर मनीराम अहिरवार जी जो कि राजमहल की सुरक्षा में सेवादार के रूप में काम करते थे।

सन 19 42 में चीचली महाराज जी जब पढ़ने लिखने के लिए बाहर गये थे। तब महल की देखभाल व सुरक्षा के लिए वीर बहादुर मनीराम अहिरवार जी को राजा साहब ने सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का जुम्मा सौंपे तभी दिनांक 23 अगस्त 19 42 को अंग्रेजी सेना महल पर कब्जा एवं लूटने आये। उनसे भीषण युद्ध वीर मनीराम अहिरवार जी ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करते हुए अंग्रेजी सेना को लहूलुहान कर व उन्हें परास्त कर गांव से खदेड़ा। युद्ध में वीर मनीराम अहिरवार जी पर चलीं गोली में गांव के महान क्रांतिकारी वीर मंशाराम जसाटी जी और वीरांगना गौरादेवी जी की शहादत हुई। मनीराम जी युद्ध करते रहे। दूसरे दिन गिरफ्तारी हेतु अंग्रेजी सेना चीचली आई गांव के अनेक आन्दोलित युवाओं को साथ ले गई। वीर मनीराम भूमिगत हो गये, बाद में उन्हें छल कपट से अंग्रेजी सेना अपने जाल में फंसा कर

ले गई। उन पर अत्याचार, दमन व प्रताड़ना दी कि वह चीचली गोंड महल की सुरक्षा छोड़ कर अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को अंग्रेजी सेना में गुलामी एवं बेगारी करने हेतु सेना में भर्ती कराये। उनकी इस शर्त को न मानने और जबाब में कहा कि मैं गोंड महल की सुरक्षा के लिए जान तक देने के लिये तैयार हूँ, पर तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा।अंग्रेजों ने वीर मनीराम जी के प्राण ले लिया, वीर मनीराम अहिरवार जी ने हंसते हंसते मातृभूमी पर कुर्बानी देकर अनुसूचित जनजातियों के स्वाभिमान के लिए शहादत दी ।लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास में ऐसे बलिदानी का नाम कम लिखा गया है। जबकि चीचली में अंग्रेजी सेना से उन्होंने गोलीओं से सामना कर गोंड महल के लिए युद्ध लडा। 21 नबम्वर 2022 को मध्यप्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्री महेन्द्र सिंह (पूर्व डिप्टी कलेक्टर) पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष एवं कांग्रेस वचन पत्र 2023 सदस्य के मुख्य अतिथि में, श्री एस एस सूरवंशी जी (सीआईडी पुलिस निरीक्षक) व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय डॉ. अम्बेडकर विचार मंच व श्री महेश नंदमेहर जी भोपाल जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग भोपाल के विशिष्ट अतिथि एवं अमर शहीद वीर मनीराम अहिरवार जी के उत्तराधिकारी सुपौत्र मूलचन्द मेधोनिया की अध्यक्षता में तथा मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव श्री विक्रम चौधरी जी, श्री हेमंत नरवरिया जी नर्मदापुरम संभाग प्रभारी मध्यप्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग वरिष्ठ नेता, सरपंच उपसरपंच पंच कल्याण समिति मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री बलवान सिंह कुशवाहा जी, जगदीश राण जी, चिंतामण जी, मुकेश चौधरी जी, इत्यादि नेताओं और सामाजिक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में शहीद वीर मनीराम अहिरवार जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर भोपाल जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग भोपाल के अध्यक्ष श्री महेश नंदमेहर जी ने कांग्रेस वचन पत्र 2023 के लिए सुझाव व मांग पत्र मुख्य अतिथि जी को दिया। तथा भोपाल अजा कांग्रेस अध्यक्ष श्री महेश नंदमेहर जी ने कहा कि हमारे अनुसूचित जाति के महान क्रांतिकारी वीर सपूत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं अनुसूचित जाति के प्रदेश भर के सामाजिक संगठनों की मांग है कि हमारे वर्ग के एकमात्र शहीद को इतिहास में स्थान नहीं दिया है।

अनुसूचित के लोगों द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही है। तथा नाराजगी बड़े पैमाने पर भी जताई जा रही है कि कांग्रेस के शासन काल में हमारे ऐसे क्रांतिकारी का सम्मान न देना और उपेक्षा कर अन्याय हुआ है। यह मुद्दा हर बार विधानसभा /लोकसभा चुनाव में बीजेपी और राजनैतिक पार्टीओं के द्वारा उठाकर कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है । अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का जनाधार को प्रभावित हर चुनाव में भी राजनैतिक दलों द्वारा लाभ उठा कर कांग्रेस को नुकसान किया जाता है। सभी उपस्थित अनुसूचित जाति के वरिष्ठ समाजसेवी, पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं के द्वारा अमर शहीद वीर मनीराम अहिरवार जी को पुष अर्पित कर भावभीनी विनम्र श्रध्दांजलि अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर नमन किया और एक मत से पुरजोर मांग की है कि वीर मनीराम अहिरवार जी को शहीद दर्जा दिया जाये।

गाडरवारा किसान मोर्चा ने तीन काले कानून सरकार के द्वारा वापसी पर जश्न मनाया गया

मूलचन्द मेधोनिया भोपाल मोबाइल 8878054839 गाडरवारा ।

नरसिंहपुर। 21 नवंबर 2021को संयुक्त किसान मोर्चा द्धारा 385दिन तक तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की बॉर्डर को घेरते हुए आन्दोलन के परिणाम स्वरूप मोदी स्कार को काले कानून बापिस लेने माफी मांगते हुए घुटने टेकना पड़े। आज का दिन किसानी के लिए खुशी का दिन है जिसे किसान पूरे देश में मोमबत्ती, दीप जलाकर, फूल बांटकर, मिठाईयां बांटकर पूरे देश में जश्न मना रहे हैं। आज गाडरवारा संयुक किसान मोर्चा ने पचामा, एवं

गाडरवारा मंडी में मोमबत्ती जलाकर जश्न मनाया। साथ ही मोर्चे द्धारा देश के सभी राजधानियों में शेष मांगो को लेकर जो सरकार ने लिखित आश्वासन के बाद बादा खिलाफि की उन्हे लेकर 26नवम्बर को भोपाल राजभवन मार्च करेंगे। आज का दिन किसानो को जीत के एक वर्ष होने पर खुशी का दिन है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने सेवा सहकारी समिति से मांगी जानकारी

मूलचन्द मेधोनिया भोपाल मोबाइल 8878054839

इमलिया। गाडरवारा जिला नरसिंहपुर सेवा सहकारी समिति इमलिया पिपरिया तहसील गाडरवारा की सूचना अधिकार के तहत मांगी जानकारी, संयुक्त किसान मोर्चा नरसिंहपुर स्यरूद्धारा 26नवंबर 2022को भोपाल राजभवन मार्च अभियान के तहत स्वतंत्र किसान संगठन के नेता बृजमोहन कौरव एवं किसान सभा के अध्यक्ष जगदीश पटेल द्धारा गांव गांव भ्रमण जारी है, इस दौरान सेवा सहकारी समिति इमलिया पिपरिया में भारी अनियमित्तताओ की शिकायते मिली, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, एक सप्ताह पूर्व के काटे गए परमिट का किसानों को खाद नहीं मिल रहा है जबकि हस्ताक्षर खाद प्राप्ति पर करा लिए हैं। 13एकड़ की ऋण पुस्तिका पर केवल 4000का खाद दिया है जबकि लिमिट आप सभी जानते हैं। समिति प्रबंधक के दर्शन नहीं होते कर्मचारियों का कहना है जितना आदेश है उतना हम कर पायेंगे। समिति प्रबंधक से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया फोन रिसीव नहीं किया। किसान खाद न मिलने से चिंतित हैं। मोर्चा के किसान नरेश कौरव ने सूचना अधिकार के तहत सोसायटी की बिंदुबार जानकारी समिति से 10रु शुल्क जमा के साथ मांगी है, प्रबंधक ने सूचना अधिकार के तहत न आने का हवाला दिया है, मांगी जाने वाली जानकारी आवेदन की पावती दी गई है, किसी भी तरह जानकारी किसानों को मिले यह किसान मोर्चा मांग करता है।

1 जून से अभी तक खाद के काटे गए परमिट की जानकारी।
2PDS राशन वितरण के दिन खाद वितरण नहीं करने के नियम की जानकारी।
3 समिति इमलिया में खाद किस वाहन से कब कितना लाए, एवं इमलिया पिपरिया में कितनी जगह स्टॉक होकर वितरण होता है।
4प्रति एकड़ खाद लिमिट की जानकारी।
5 कार्यालय खुलने बंद होने का समय, खाद वितरण के दिन कोन से निर्धारित है।
6 खाद का स्टॉक कितनी जगह होता है।
7 परमिट कहां कटते हैं, वितरण कहां होता है।

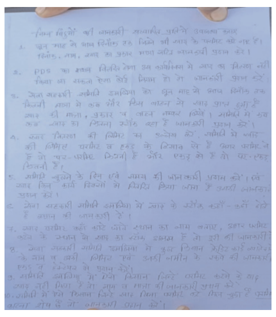

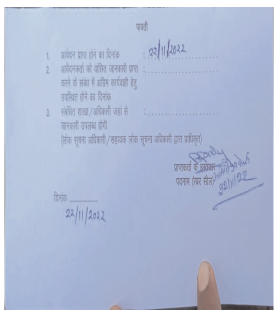

8 कुल खातेदारों की सूची, कितनी जमीन, कर्ज लिमिट नगद एवं वस्तु रूप में कितनी।
9 वर्तमान में कट चुके परमिट में कितने किसानों को खाद नहीं मिला।
10 किसानों की खाद की पचासों हजार की लिमिट होते हुए उनके द्वारा पूरा खाद चाहने पर भी तीन से पांच हज़ार तक के ही परमिट काटे गए ऐसा क्यों।

बाल कविता

स्कूटर की भी बना देते हैं, हम कार।
जब बैठ जाते हैं उस पर, हमारे चच्चा-चाची और हम चार।
फिर भी जो थोड़ी सी बच जाती है, जगह खाली।
बीच में लिफ्ट मांगने आ जाती है, आंटी पड़ोस वाली।
उसको देखकर, मेरी चाची जो अपना आपा खोती है।
बेचारे मेरे चच्चा को, सड़क पे ही धोती है।
मगर मास्टर जी,आप इस पिटाई के विषय में सुनकर।
ऐसे क्यों सिमटते हो ?
क्या आप भी मास्टरनी जी से
ऐसे ही सड़कों पे पिटते हो?

कवि आशीष चौहान।
बाड़ी जिला रायसेन मध्य प्रदेश

कलेक्टर भार्गव ने आमजन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील

❑विदिशा

कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले के सभी नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है कि सभी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। कलेक्टर भार्गव ने कहा कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य गतिशील है। इस कार्य हेतु समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों में प्रातः 10 बजे से सांय पांच बजे तक उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी बीएलओ के द्वारा डोर-टू-डोर जाकर कार्य कर रहे हैं। सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। कलेक्टर भार्गव ने कहा कि मतदाता बंधु अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप इंस्टॉल कर ऐप के माध्यम से भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए वर्ष में चार बार सुविधा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2023, एक अप्रैल 2023, एक जुलाई 2023 एवं एक अक्टूबर 2023 को जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो रही है वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। आयोग द्वारा 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता बनने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदाय की है।

आवश्यकता

युवा प्रदेश नेटवर्क

मध्यप्रदेश के सभी जिले व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त किये जाने है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें।

युवा प्रदेश नेटवर्क,
प्रधान संपादक-नागेश नरवरिया
मो.- 9425156055-9755364204

26-27 नवंबर को दर्शनों के लिए रखी पवित्र अस्थि कलश

सांची बौद्ध महोत्सव में शामिल होंगे श्रीलंका वियतनाम और जापान के अनुयायी

❑रायसेन

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची में कोरोना के दो साल बाद मप्र शासन व श्रीलंका महाबोधी सोसायटी सांची द्वारा 70वां सांची वार्षिकोत्सव 26 व 27 नवंबर को होगा। इसमें श्रीलंका वियतनाम व जापान सहित अन्य देशों से भी बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। महोत्सव में आने वाले पर्यटकों व अनुयायियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मेले में एएसएफ की 2 कंपनियों के साथ ही बाहर से 200 जिला पुलिस बल की टुकड़ी को तैनात किया जाएगा। दो दिवसीय सांची महोत्सव में गौतम बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोग्गलान के पवित्र अस्थि अवशेष को दर्शनों के लिए रखा जाएगा। पूजा अर्चना के बाद बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अस्थि कलश को सिर पर रखकर सांची स्तूप की परिक्रमा भी की जाएगी। सांची मेले में इस बार एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इस लिहाज से पांच स्थानों पर की व्यवस्था भी की गई है। श्रीलंका के राजदूत और प्रदेश के तीन मंत्री भी आएंगे महाबोधि महोत्सव में भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंद मोरगोड़ा के अलावा संस्कृति मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर, स्वास्थ्य पार्किंग मंत्री मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और एडीजी अनुराधा शंकर भी शामिल होंगी।

26 नवंबर को जातक कथा पर आधारित तृष्णा नाट की प्रस्तुति धन्नूलाल सिन्हा व उनके साथी कलाकार देंगे। इसी दिन अफजल हुसैन के साथ अन्य कलाकर ध्रुपद शैली में बुद्धम शरण गच्छामि गायन की प्रस्तुति देंगे। 27 नवंबर को सागर के जुगल किशोर नामदेव के साथ कलाकारों द्वारा बुंदेलखंड के बधाई व नौराता लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी दिन रात में कवि सम्मेलन होगा।

अठारह वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक युवा का नाम मतदाता सूची में दर्ज होः राजेश कौल

रायसेन। जिले में चलाए जा रहे मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौल ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि राजनैतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त किए जाते हैं, जिनका मतदाताओं से सीधा सम्पर्क होता है। उन्होंने कहा कि बीएलए अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र में सभी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तथा उनकी मतदाताओं से सतत् सम्पर्क भी होता है। मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जरूरी है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। साथ ही ऐसे नाम भी मतदाता सूची में ना जुड़े हो जिनकी मृत्यु हो गई है या वह कहीं ओर रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के तहत बीएलओ द्वारा अपने मतदान केन्द्र पर बैठकर आवेदन लिए जा रहे हैं तथा घर-घर दस्तक भी दी जा रही है।

स्कूल के सामने तंबाकू, सिगरेट बेचने वालो के विरुद्ध की गई कार्यवाही

युवा प्रदेश ❑शहडोल

कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर एस पांडे के निर्देशानुसार आज जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम सिंहपुर क्षेत्र का भ्रमण तंबाकू नियंत्रण टीम द्वारा कई विद्यालयों का किया गया। भ्रमण के दौरान तंबाकू नियंत्रण टीम ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को तंबाकू, सिगरेट जैसे अन्य धूम्रपान सामग्री का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। साथ ही तंबाकू नियंत्रण टीम के नोडल अधिकारी डॉ पुनीत श्रीवास्तव एवं फूड ऑफिसर श्री रामेंद्र सोनी द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मापदंडों के अनुसार विद्यालय के बाहर सिगरेट तंबाकू बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर 500 रुपए का चालान काटा गया।

मोतियाबिंद की जांच शिविर में 315 मरीजों ने कराया पंजीयन

विदिशा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर के अस्पताल परिसर में आज बुधवार को मोतियाबिंद की जांच हेतु नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि श्री कैलाश रघुवंशी ने मां सरस्वती जी की पूजन अर्चना कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया।इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कल्बे अब्बास जैदी, नेत्र सहायक श्री सुनील जैन, सदुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर के नेत्र चिकित्सकों समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। नेत्र परीक्षण शिविर में कुल 315 मरीजों का पंजीयन किया गया था। जिसमें से 90 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए जिन्हें शासकीय वाहनों द्वारा सदुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर लेंस प्रत्यारोपण हेतु भेजा गया है। आनंदपुर सदुरु सेवा ट्रस्ट में निशुल्क लैंस प्रत्यारोपण किया जावेगा। इसके पश्चात मरीजों को 25 नवंबर को निशुल्क शासकीय वाहनों से वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर भेजा जाएगा।

जनजाति कार्य विभाग जिला ग्वालियर संभाग ग्वालियर के कारनामे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए : महाराज सिंह राजोरिया

युवा प्रदेश ❑ग्वालियर

मूलचन्द मेधोनिया भोपाल
मोबाइल 8878054839

आज प्रेस को जारी विज्ञप्ति में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक एवं नगर पालिका परिषद डबरा के पूर्व चेयरमैन महाराज सिंह राजोरिया ने बताया कि विधानसभा में गलत जानकारी देना फर्जी छात्रवृत्ति के घोटालों में शामिल फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले के अपराधों में नाम शामिल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने आदेशों में राज्य प्रशासन सेवा के अधिकारी बनाया और सहायक आयुक्त का प्रभार दिया विनय सक्सेना द्वारा विधान सभा क्वेश्चन लगाए गया था विधानसभा प्रश्न का क्रमांक 1583 जिसका उत्तर 14 मार्च 2022 तक दिया जाना था, जनजाति कार्य विभाग जिला ग्वालियर के प्रभारी सहायक आयुक्त एचबी शर्मा इनका मूल पर प्राचार्य है इनके द्वारा विधानसभा को गलत जानकारी भेजी गई है विधानसभा में गलत उत्तर देना काफी बड़ा गंभीर अपराध है विधानसभा में गलत जानकारी देना गंभीर मामला है, यह प्राचार्य भी जनजाति कार्य विभाग के हैं वर्तमान में इनकी पदस्थापना कार्यालय संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग संभाग ग्वालियर में है शासन ने इनका स्थानांतरण संभागीय उपायुक्त कार्यालय के विकल्प पर किया था संभागीय उपायुक्त का कर्तव्य था कि इनको ग्वालियर संभाग में जनजाति कार्य विभाग के किसी भी विद्यालय में प्राचार्य के रिक्त पर पदस्थ किया जाना था यदि ग्वालियर संभाग में पद रिक्त नहीं था तो इन्हें मध्यप्रदेश में किसी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थ हेतु प्रदेश शासन अनुसूचित जाति जनजाति विभाग अथवा आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश को प्रस्ताव भेजना चाहिए था जो आज तक नहीं भेजा गया है एच बी शर्मा के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कब कार्यवाही की जाएगी तथा कलेक्टर और कमिश्नर क्यों वचाना चाहते हैं जवकि प्रदेश के मुख्य मंत्री भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सभाओं में भ्रष्टाचारियों को बक्से ना जाने की बात कह रहे हैं,*यह आरोप लगाया है महाराज सिंह

राजोरिया ने जो डबरा नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन है वह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक है* आप देखें कितने गलत आदेश किए जा रहे हैं दोषियों को बचाया जा रहा है महाराज सिंह राजोरिया ने बताया कि दर्जनों नहीं सैकड़ों शिकायतें कलेक्टर ग्वालियर से लेकर संभाग ग्वालियर सहित शासन और मुख्यमंत्री को की गई है लेकिन सभी शिकायतें कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय में धूल खा रही है राजोरिया ने बताया है कि जनजाति कार्य विभाग ग्वालियर के एचबी शर्मा विभाग के प्राचार्य हैं और इनको सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ग्वालियर का प्रभार देते समय इन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी मानकर आदेश जारी कर दिया जबकि यह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं है राजोरिया ने मांग की है कि इन्हें तत्काल सहायक आयुक्त के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, इसी प्रकार श्रीमती उषा पाठक को तत्कालीन कलेक्टर ने जांच में दोषी पाया सभी शिकायतों में लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए जांच रिपोर्ट में उषा पाठक को निलंबित करने की सिफारिश की है और विभाग की संपूर्ण जांच जांच दल बनाकर करने की अनुशंसा करते हुए आयुक्त ग्वालियर को वर्ष 2019 में ही भेजी गई लेकिन आज तक न निलंबित किया गया है नहीं किसी प्रकार की कोई जांच की गई है एक दूसरे आरोप में इनके विरुद्ध अजाक थाने में दर्ज अपराध में आरोपी है प्रकरण ग्वालियर न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन फिर भी इनको आज तक निलंबित नहीं किया गया यदि अनुसूचित जाति जनजाति का अधिकारी होता तो निलंबित ही नहीं उसके सब कर्म कर दिए जाते हैं यह जातिवाद का खुला आरोप है महाराज सिंह राजोरिया में भी दर्जनों शिकायतें शासन प्रशासन से की है लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। राजोरिया ने प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग की है कि इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए और दिए गए परिवारों से तत्काल मुक्त किया जाए। राजोरिया ने प्रेस को एचबी शर्मा को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मानकर प्रभार देने का आदेश और उषा पाठक के विरुद्ध की गई जांच रिपोर्ट तथा न्यायालय के दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं जिसमें यह आरोपी है।

धर्मेंद्र अहिरवार स्टारर शॉर्टफिल्म हत्या राही प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर हुई रिलीज़

युवा प्रदेश ❑ विदिशा

सिरोंज में जन्मे धर्मेंद्र अहिरवार की हत्या शॉर्टफिल्म, राही प्रोडक्शन के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर 15 नवंबर को रिलीज़ कर दिया गया है । धर्मेंद्र ने इसमें लीड रोल में है । राही प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फ़िल्म की शूटिंग मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सेकंड लॉकडाउन के दौरान हुई थी । हत्या फ़िल्म को प्रवीण कुमार पाण्डेय व धर्मेंद अहिरवार ने प्रोड्यूस किया है । फ़िल्म की मुख्य भूमिका धर्मेंद्र अहिरवार व जाह्नवी चतुर्वेदी निभा रहे है। यूट्यूब पर यह फ़िल्म रिलीज़ होते ही फ़िल्म की कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है । फ़िल्म में तन्मय और मीता की प्रेम कहानी देखने को मिलती है । फ़िल्म की कहानी ऐसे शुरू होती है , तन्मय बहुत ही उदास और गहरे सदमे में डूबा हुआ है । उसी समय उसकी मां का फोन आता है । और वह कहती है कि अपना ख्याल रखना और मीता को भूल जाओ । तन्मय , मीता की दोस्त शिल्पा के पास जाता है और उससे शिल्पा के बारे में पूछता है , उसे लगता है कि मीता के बारे में उसे ज़रूर पता होगा । लेकिन वहां से भी उसे निराशा हाथ लगती है । जब तन्मय तालाब के

किनारे अकेला बैठा होता है तो रजत आकर उसे दिलासा देता है कि हम सब मिलकर मीता को ढूंढ लेंगे। मीता कैद है और उसकी शादी होने वाली है। देर रात तन्मय और मीता वीडियो चैट पर बात करते हैं जहां मीता आत्महत्या करने की बात करती है, वहीं तन्मय भी उसके इस फैसले में शामिल हो जाता है। हादसे के आखिरी वक्त में मीता रुक जाती है और तन्मय फांसी के फंदे पर लटक जाता है। दर्शकों को यह कहानी अंदर से झकझोर देती है । और समाज के सामने एक प्रश्न छोड़ देती है । फ़िल्म में धर्मेंद्र और जाह्नवी ने अपने अपने क़िरदार को बखूबी निभाया है । इस फ़िल्म के लेखक व निर्देशक शुभम विश्वकर्माहै । इसमें मुख्य में मुख्य कलाकारों धर्मेंद्र व जाहन्वी के आलावा अनुराग जैन ' अनु ', स्वाती मंदवारिया, पुष्पा नाथ, व अनिमेष श्रीवास्तव ने अभिनय किया है । फ़िल्म में

सिनेमेटोग्राफी बॉबी सिंह , एक्जीक्यूटिव **प्रोड्यूसर**-अंशुमान सिंह , एडिटर- सचिन गौर , सोनू कुमार , **कास्टिंग**- सनित स्वामी , कॉस्ट्यूम- पूजा कंडारे, प्रोडक्शन **मैनेजर**- बसंत मोहने, **लाइट**- किश, मेकअप- निशा, साउंड-देवांश सैनी , **डबिंग**- यश सोनी , **म्यूजिक**- आदित्य सिंह राठौर , **स्टिल फोटोग्राफर**- आलोक टंडन , प्रांजुल साहू , अमन केशरवानी , उत्कर्ष आर्या ने काम किया है । दर्शक **शॉर्टफिल्म**- हत्या को राही प्रोडक्शन चैनल पर देख सकते है ।

बाबा साहेब का संविधान

आओ सब मिल नमन करें हम,भारत के उस संविधान को।
समता का पाठ पढ़ाया जिसने, दुनियां को उस विधान ने।
लोकतंत्र को मजबूत बनाया, जिस बाबा साहेब के संविधान ने।
जिस बाबा साहेब के संविधान ने।।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुम्बई से लेकर गुवाहाटी तक।
एक भारत, श्रेष्ठ भारत का मंत्र सिखाया जिस हिंदुस्तान ने।।
सत्य, अहिंसा, न्याय का राह दिखाया, भारत के उस संविधान ने।।
जहां गूंजते थे साथ अजान अल्लाह के और कीर्तन श्री राम के।
दुष्टों ने बैर कराया आपस में,दंगा भी हुआ सिक्ख-हिन्दू - मुसलमान के।
भागे फिरंगी सात समुंदर पार,देश को फिर से जगाया ;
गांधी, सुभाष,पेरियार,अम्बेड़कर और बुद्ध के ज्ञान ने ।।
मंदिर - मस्जिद के झगड़ों ने, जहां बाँट दिया इंसान को।
अदालत में न्याय मिला आज ,उस अल्लाह और भगवान को।
साहिष्णुता और भाईचारे का संदेश दिया,उस भारतीय संविधान ने ।।
सभी जीवों में दयाभाव का प्रेम जगाया,मानव को मानव का बोध कराया।
नीति -निर्देशक, मूल अधिकार और कर्त्तव्य बताया,
शोषित,पीड़ित,दलित जनों का सोया भाग्य जगाया।
जाति,धर्म,वंश भेद मिटा कर फिर से ,देश को संबल बनाया
भारत के उस संविधान ने।
आओ-------संविधान ने ।।

भीम कुमार
गांवाँ
गिरिडीह,झारखंड

पंजीकृत किसानों के अतिरिक्त धान का उपार्जन अन्य लोगों से नही होना चाहिए- कलेक्ट्रेट

धान खरीदी की सभी व्यवस्थाएं केन्द्रों में सुलभ रहें- श्रीमती वंदना वैद्य

शहडोल। कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में धान उपार्जन की तैयारी समीक्षा बैठक में लेकर खरीदी केन्द्रों के प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे पंजीकृत किसानों के अतिरिक्त अन्य लोगों या व्यापारियों आदि से किसी भी स्थिति में धान की खरीदी नही करें, ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान की क्वालिटी खरीदी के पूर्व परख लें तथा शासन के निर्देशानुसार ही खरीदी करें। बैठक में धान खरीदी की आवश्यक तैयारियां, सावधानियां आदि की विस्तार से जानकारी ली साथ ही धान खरीदी के बाद उसमें स्टैंसिल तथा लगाई जाने वाली स्लीप की भी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के तुरंत बाद परिवहन व्यवस्थाएं मुकम्मल होना चाहिए जिससे अनावश्यक रूप से परिवहन का बोझ न बढ़े, सोमवार से शुक्रवार तक ही खरीदी की जाएगी, शुक्रवार को आने वाले कृषक की धान शेष रहने पर उनकी तौलाई शनिवार को की जाएगी तथा शनिवार एवं रविवार को परिवहन की व्यवस्थाएं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि धान भण्डारण हेतु जिले में पर्याप्त कैपिसिटी उपलब्ध है । बैठक में अन्य आवश्यक भी दिशा-निर्देश दिए गये।

पुष्पराजगढ़ विधायक के नेतृत्व में राहुल गांधी जी का बुरहानपुर में किया गया स्वागत यात्रा में हुए शामिल

युवा प्रदेश ❑ अनूपपुर

पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शहडोल संभाग के आदिवासी नेता फुंदेलाल मार्को ने अनूपपुर जिले के अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बुरहानपुर पहुंचकर राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत किया।एवं भारत जोड़ो पर यात्रा में शामिल हुए।राहुल गांधी जी के साथ 16 किलोमीटर की यात्रा भी तय की।इस यात्रा में प्रमुख रूप से पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को,भारत जोड़ो पदयात्रा के सह समन्वयक संतोष कुमार पाण्डेय,यूथ कांग्रेस महासचिव अनुज मिश्रा,राजीव शर्मा,यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को,नौसेरमा भाई,यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमरकंटक वीरू तंबोली एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में राहुल गांधी जी का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत,वंदन, अभिनंदन कर भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए।

कलेक्टर ने दुर्घटनाओं को रोकने सभी आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश

❑सीहोर

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन दल को विशेषकर शाम के समय एवं रात्रि में ब्रेथ एनालाइजर से शराब का सेवन करने वाले चालकों पर कार्यवाही करने तथा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही कर ड्रायविंग लायसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ सिंह ने वाहनों की ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए हाईवे के टोल नाकों के पास स्पीड रडार गन द्वारा वाहनों पर कार्यवाही करने तथा हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए अध्ययन कर ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा में जागरूकता के लिए निरन्तर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उन्होने कहा कि रोड निर्माण एजेंसी जिले में सभी प्रकार की सड़कों का सर्वे कर यह सुनिश्चित करें कि सभी सड़कों पर संकेतक, पुल एवं पुलिया क्षतिग्रस्त न हो।

पढ़ें लिखे लोग आंबेडकरी आंदोलन में सहयोग करते नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग ही आंबेडकरी आंदोलन को रुकने नहीं देते है

चक्रधर जांभुळे,
एक्जीक्यूटिव मेंबर, पी बी एस पी

बिलासपुर। दिनांक 20 नवंबर 2022 इतवार को पे बैक टू दि सोसायटी प्रोग्राम छत्तीसगढ़ प्रदेश की और से बिलासपुर स्थित राज्य स्तरीय एक दिवसीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मुख्य मार्गदर्शक तथा मुख्य अतिथि धीमंत पी आर अंबेडकर थे, डॉ जी सी भारद्वाज, राष्ट्रीय जनरल महासचिव लिटररी ऑपरेशन तथा गुलाब विश्वकर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, महिला ऑपरेशन यह मुख्य मार्गदर्शक थे। धीमंत पी आर अंबेडकर इन्होंने मुख्य मार्गदर्शन किया और भारत में जो भी समस्या है यह जाती की समस्या को, इसे समझना जरूरी है। जब तक जाति को समझते नहीं तब तक उसका हल भी निकाल नहीं सकते। जाती क्या है? जाती किसने बनाई है? जाती बनाने का उद्देश्य क्या है? भारत की जाती संस्था को कोण निर्मूलन कर सकते हैं और इस जाती संस्था का निर्मूलन का मार्ग क्या है? इस विषय पर धीमंत पी आर अंबेडकर, राष्ट्रीय संयोजक, पे बैक टू दि सोसायटी प्रोग्राम ने मार्गदर्शन किया। पुरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से करीब दो सौ बुद्धिजीवी व्यक्ति उपस्थित थे। महात्मा ज्योतिबा फुले, रामास्वामी इ व्ही पेरियार, नारायणा गुरु, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर के चौथे गुरू जॉन डिव्ही,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तथा महानायक कांशीराम जी इनके विचारों पर प्रकाश डाला। भारत की जाती समझने से पहले जाती का विलोम शब्द क्या है यह समझना जरूरी है और जाती का विलोम शब्द है सहकारिता यह बात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने पांच वर्षीय नियोजन में बतायी है उस आधार पर सहकारिता को बढ़ावा दे कर जाती को समाप्त कर सकते हैं। आज के जमाने में युद्ध के हथियार बोथडे हुए हैं इसलिए सोच विचार कौशल्य हथियार से दूश्मन से मुकाबला कर सकते हैं पे बैक टू दि सोसायटी प्रोग्राम के माध्यम से हमें इस देश में महान अशोक का भारत जो सभी के लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा समान हो और डॉ बाबासाहेब आंबेडकर का प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए संकल्पित है। इसलिए हम भारतवर्ष में टप्पा टप्पा से एक हजार, दस हजार, एक लाख तथा दस लाख बुद्धिजीवी ट्रेनर बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्य स्तरीय सम्मेलन में अध्यक्षता रामजी विश्वकर्मा ने किया और इसी साल के अंत तक पांच सौ बुद्धिजीवी व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर समाज को समर्पित करने का संकल्प किया। अधिवेशन में धीमंत गौतम वावरे, राष्ट्रीय ट्रेनर तथा एक्जीक्यूटिव मेंबर ने समय को ध्यान में रखते हुए छोटा भाषण किया। अधिवेशन में धीमंत चक्रधर जांभुळे, राष्ट्रीय एक्जीक्यूटिव मेंबर ने केवल पढ़ें लिखे लोग तथा बुद्धिजीवी व्यक्ति इन में अंतर बताता। दिनांक 18 मार्च 1956 में डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने मुझे पढ़ें लिखे लोगों ने धोखा दिया था यह बात कही थी इस बात में सच्चाई है और आज भी पढ़ें लिखे लोग समाज में आंबेडकरी आंदोलन को केवल कोसने काम कर रहे हैं लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति आंबेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु आगे आ रहा है। धीमंत चक्रधर जांभुळे ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि पढ़ें लिखे लोग याने मिट्टी का कच्चा घड़ा और बुद्धिजीवी व्यक्ति यह भट्टी में पका हुआ घड़ा जिसमें कितना भी पानी डालकर भी फुटने वाला नहीं है या गलनेवाला नहीं है ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को साथ लेकर महान अशोक और डॉ बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों पर चलकर महान अशोक का भारत तथा प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है। धीमंत विजय सर, भिकादीन आंखें इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। रात 9-00 वजे से 12-00 बजे तक कवी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें धीमंत गुलाब विश्वकर्मा, डॉ भारद्वाज, गीता विश्वकर्मा, बृहस्पति हिरवानी, धीमंत पी आर अंबेडकर, जगतारन प्रसाद डहरे, हरीश पांडल,खुटियारे जी, टेकचंद पांडल,कोमल दिवाकर,इंद्र कुमार भारद्वाज ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया।

जनप्रतिनिधियों और मुख्य नगरपालिका अधिकारी आपस में सामंजस्य स्थापित कर करे अनूपपुर का विकास : श्रीमती डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी

युवा प्रदेश ❑ अनूपपुर

2022 के नगरीय निकाय चुनाव में विजय का ताज हासिल कर जनता की समस्याओं का समाधान करने की जवाबदेही तय करने वाले जनप्रतिनिधि आज स्वयं समस्याओं से घिरे नजर आ रहे हैं वार्डो में बढ़ती समस्याओं को लेकर जनता ने भी अब जनप्रतिनिधियों पर तंज कसना शुरू कर दिया है मूलभूत की सुविधाएं नही मिलने से वार्डवासी भी त्रस्त हो चुके हैं। जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी अपना आपा खो दिया और प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक में सामान्य सी बात को लेकर नगर पालिका परिसर में हंगामा हो गया । इस बीच जनप्रतिनिधियों और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के बीच सामंजस्य की सरासर कमी नजर आ रही है जिसके कारण शहर का विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ।यह कहना है नगरपालिका अनूपपुर के वार्ड नंबर 7 की पार्षद श्रीमती डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी का ,पार्षदो की जो भी समस्याएं हैं वे शालीनता से अपनी समस्याएं अवगत कराएं ,जिसका निराकरण मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाए। खुद की परवाह न करते हर परिस्थितियों में हमको जन मानस के लिए सदैव समर्पित होकर पूरी निष्ठा,ईमानदारी से अपने कार्यों को करने के जनता ने अपना मत दिए है । व्यगतिगत हितों और अहम से दूर हो कर नगर के विकास के लिए परिषद हो तो बेहतर है जिस उद्देश्य को लेकर जनता ने हमें चुन कर परिषद् में भेजा है हम उनके उम्मीदों पर खरे उतरे।

संपादकीय

मोदी सबसे कह रहे हैं यह युद्ध का समय नहीं है, मगर सेना पाक लाने की बात कह रही है!

सेना की उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कार्रवाई वाला बयान चौंकाने वाला है। सेना का काम बयान देना नहीं है। उसका काम सरकार के आदेश पर ऑपरेशन करना है। सेना को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। भारत के कई सत्ताधारी दल के नेताओं के बयान कई बार सरकार के सामने असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट भी परेशान कर देती हैं। ऐसे में उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कार्रवाई वाला बयान भी कुछ ऐसा ही है। यह बयान पाकिस्तान-चीन समेत दुनिया के भारत विरोधी देशों के लिए चौंकाने वाला और उन्हें लामबंद करने वाला है। ये बयान भारत का विरोध करने वाले देशों को शोर मचाने का एक और मुद्दा थमा देगा। उन्होंने पारिकस्तान द्वारा कब्जा किए कश्मीर पर कार्रवाई के बारे में पूछे गए सवाल पर ये बात कही। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार जब आदेश देगी, सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश की पालना के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी आदेश देगी सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी लॉन्चपैड पर करीब 160 आतंकी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले तीन नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक रैली में भी इसी तरह की मांग उठी थी। वे वहां एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से लोगों ने कहा- पीओके भी अब भारत में चाहिए। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा था। धैर्य रखिए। धैर्य रखिए। राजनाथ हिमाचल के वीर जवानों को लेकर बात कर रहे थे कि रैली में मौजूद लोगों ने पीओके चाहिए, के नारे लगा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू-कश्मीर में हो रही टार्गेट किलिंग पर कहा कि राज्य में आतंकवाद को रोकने के लिए काफी काम किया गया है। इससे बौखलाए आतंकियों की तरफ से कभी पिस्टल, कभी हथियार इस तरफ भेजने के प्रयास किए जाते हैं और निहत्थे लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में काफी बदलाव आया है। राज्य में आतंकवाद पर लगाम लगी है। देखा जाये तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पूरा बयान ठीक है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में साकार हो रहा है लोकल फॉर वोकल का सपना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मई, 2020 में देशवासियों के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा के साथ ही लोकल, वोकल और ग्लोबल का संदेश दिया था तब लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इस संदेश का असर इतने गहरे तक जाएगा और बहुत कम समय में यह समूचे देश की आवाज बन जाएगा। असल में कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल के रह गई है तो चीन का मुकाबला लोकल के लिए वोकल होकर ही किया जाना संभव माना गया। हालांकि देश में चीनी उत्पादों के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना है पर आंकड़ों में बात करें तो अभी भी चीन से निर्यात के आंकड़े नीचे नहीं आये हैं। इसके लिए अभी देश में बहुत कुछ किया जाना जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस साल देश में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला की अपनी विशिष्ट पहचान है और समूचे देश की झलक इस व्यापार मेले में देखने को मिल जाती है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में देशी विदेशी दर्शकों को मिनी भारत की झलक कराता है। इस बार खास बात यह है कि लोकल, वोकल और ग्लोबल को इस मेले में साकार किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि इस दफा व्यापार मेले में 95 प्रतिशत उत्पाद स्वेदशी या यों कहें के देश में ही बने हुए उत्पाद मिल रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में लोकल फोर वोकल की थीम साकार हो रही है तो देशी विदेशी दर्शकों को यह उत्पाद भा भी खूब रहे हैं। इसे स्वदेशी या यों कहें कि लोकल को प्रोत्साहित करने का प्रमुख माध्यम माना जा सकता है तो यह भी साफ हो जाता है कि देशवासी स्वदेशी उत्पादों को भी हाथोंहाथ लेते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मई, 2020 में देशवासियों के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा के साथ ही लोकल, वोकल और ग्लोबल का संदेश दिया था तब लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इस संदेश का असर इतने गहरे तक जाएगा और बहुत कम समय में यह समूचे देश की आवाज बन जाएगा। असल में कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल के रह गई है तो चीन का मुकाबला लोकल के लिए वोकल होकर ही किया जाना संभव माना गया। हालांकि देश में चीनी उत्पादों के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना है पर आंकड़ों में बात करें तो अभी भी चीन से निर्यात के आंकड़े नीचे नहीं आये हैं। इसके लिए अभी देश में बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। दरअसल कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती हो गई थी। सबकुछ बदल के रख दिया था कोरोना ने समूची दुनिया में। देखा जाए तो आर्थिक

उदारीकरण के बाद ग्लोबलाइजेशन और आईटी क्रांति से कारोबार का जो नया ट्रेंड ऑनलाइन चला था उसे भी कोरोना बहुत हद तक प्रभावित किया। कोरोना से एक सबक और मिला कि महामारी संकट के दौर में जो कुछ आपके और आपके आसपास है वही आपका सहारा है। हालांकि यह भी हमारी अर्थव्यवस्था की खूबसूरती ही मानी जानी चाहिए कि स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हमारी परंपरा से चलते आये हैं। इसके साथ ही औद्योगिकरण के दौर में स्थानीय स्तर पर जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए वे स्थानीय जरूरतों खासतौर से खाद्य सामग्री की आपूर्ति में पूरी तरह से सफल रहे और यही कारण रहा कि सब कुछ थम जाने के बावजूद देश में कही भी खाद्य सामग्री की सप्लाई चेन नहीं टूटी। यहां तक कि हम दुनिया के कई देशों के लिए दवा की आपूर्ति करने में सफल रहे। साथ ही कोरोना का टीका उपलब्ध कराकर भारत की साख को और अधिक मजबूत किया। यह अपने आप में बड़ी बात है।

मई 2020 के प्रधानमंत्री के संदेश में स्थानीय उत्पादों को अपनाने का संदेश देने के साथ ही उसकी आवाज बनने का यानि कि उसके प्रचार-प्रसार में सहभागी बनने का संदेश भी दिया था। इसी तरह से अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में स्थानीय उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहुंचा कर यह साफ कर दिया है कि बदलते दौर में स्वदेशीकरण समस्याओं के समाधान का बड़ा माध्यम है। इससे निश्चित रूप से विदेशी का मोह भी कम होगा।

याद कीजिए, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह और उसके बाद जयपुर में आयोजित ग्लोबल खादी कांफ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी को अपनाने का संदेश दिया था। इसी तरह से ग्लोबल खादी कांफ्रेंस में ही उन्होंने दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के सामने गांधी दर्शन और गांधी जी के स्वदेशी को अपनाने का संदेश दिया और ग्रामोद्योग को अपनाने के लिए कहने के साथ ही खादी उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी। राजनीतिक प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज देश और विदेश में खादी ब्राण्ड बनकर उभरी है और खादी लोगों की पसंद बनने लगी है। एक बात और लोगों की सोच और परख में तेजी से बदलाव आया है। जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में लकड़ी और मिट्टी के बने उत्पादों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। यह प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण के प्रति सजगता की पहचान है। लोग पुरानों की ओर लौट रहे हैं तो लोकल उत्पादक पुरानों में ही नएपन का छोंकन लगा कर बाजार में उतार रहे हैं। यानि कि समय के अनुसार उनमें बदलाव कर रहे हैं डिजाइन व आज की आवश्यकता के अनुसार। लोक जूट के उत्पाद खरीद रहे हैं तो जड़ी बूटियों पर भी विश्वास बढ़ा है। मिट्टी और लकड़ी के बरतन तथा खिलौने आम होते जा रहे हैं। देखा जाए तो यह लोकल के लिए वोकल नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव का भी माध्यम बनता जा रहा है। बदलते हालातों में देश के सामने नए अवसर आए हैं। आज एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को अपनाने और उनकी ग्लोबल पहचान बनाने की आवश्यकता है। नई परिस्थितियों में दुनिया के देशों का चीन से लगभग मोहभंग हो गया है। यह देश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए नया अवसर है। ऐसे में स्वदेशी तकनीक के आधार पर औद्योगिकरण को नई दिशा देनी होगी।

कल्पवास मेला: एक पुरातन भारतीय परंपरा और जीवन मूल्य

इन दिनों कल्पवास मेला चल रहा है। यह एक पुरातन भारतीय परंपरा है। ये युगों-युगों से कल्प और कल्पान्तर से चली आ रही है। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र नदी तटों पर निवास कर भक्ति साधना करते हैं। यह कुंभ पर्व से साम्यता रखते हुए भी कई मायनों में अलग है। कुंभ की कथा विचार संस्कार और सागर के मंथन से जुड़ी है। वहीं इसका उद्देश्य अमृत रूपी तत्व को प्राप्त करना है। इसके उलट कल्पवास कायाकल्प और आत्मशुद्धि का एक माध्यम है। पुरानेपन का त्याग और नवीन का ग्रहण ही कल्प है। इस निमित ऊर्जा से परिपूर्ण किसी रमणीक नदी तीर्थ पर खास तिथियों में किया गया वास कल्पवास है। नया जीवन- नई ऊर्जा और एक बेहतर दिनचर्या के शुरुआती अभ्यास का नाम भी कल्पवास है। बात आयोजनों से जुड़ी हो तो कुंभ स्थल निश्चित और पूर्व निर्धारित है, जबकि कल्पवास के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे कल्पवास स्थल भारतवर्ष के हर हिस्से में मौजूद हैं, जहां वर्ष के अलग-अलग महीनों में कल्पवास चलता रहता है।

अदालत का सवाल सही है, आखिर 72 साल में भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून क्यों नहीं बना?

भारत में चुनाव सुधारों पर लंबे समय से बहस चलती रही है लेकिन यह सुधार इसलिए नहीं हो पाये क्योंकि जिस संस्था पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उसे कभी ज्यादा अधिकार दिये ही नहीं गये। यही नहीं, हर सरकार द्वारा अधिकारियों को चुनाव आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर उस समय नियुक्त किया जाता है जब उसकी सेवानिवृत्ति का समय नजदीक हो। इसके चलते किसी भी चुनाव आयुक्त को अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाता। देखा जाये तो भारत में चुनाव सुधार से जुड़े मुद्दे चुनावों से पहले उठते जरूर हैं लेकिन चुनाव बाद सबकुछ शांत हो जाता है। यह भी देखने को मिलता है जब कोई दल विपक्ष में होता है तो उसे चुनाव सुधारों की बहुत परवाह रहती है लेकिन सत्ता में आते ही उसके लिये यह फिजूल का मुद्दा हो जाता है या उसकी प्राथमिकता सूची से गायब हो जाता है। लेकिन अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को उठाया है इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अब चुनाव सुधारों की दिशा में आगे बढ़ेगी। सुधारों की बात की जाये तो सबसे बड़ा सुधार तो पहले चुनाव आयोग में ही करना होगा क्योंकि साल 2004 से किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। संप्रग सरकार के 10 साल के शासन में छह मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, वहीं राजग सरकार के आठ साल में आठ मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। इसलिए सरकारों की कार्यशैली और सोच पर अदालत ने सवाल उठाया है। अदालत ने सरकारों की ओर से निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं होने का फायदा उठाये जाने की प्रवृत्ति को तकलीफदेह करार दिया है। साथ ही अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लेख करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में संसद द्वारा एक कानून बनाने की परिकल्पना की गयी थी, लेकिन 72 साल गुजर गये और अब तक कानून नहीं बन पाया है जिसका फायदा सभी दलों की केंद्र सरकारें उठाती रही हैं। इसके अलावा, पांच सदस्यीय संविधान पीठ का यह कहना भी अपने आप में बहुत गंभीर है कि संविधान की चुप्पी को भुनाया जा रहा है। अदालत ने टीएन शेषन जैसे कड़े रुख वाले व्यक्ति की निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्ति की वकालत करते हुए यह भी कहा है कि संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्तों के 'नाजुक कंधों' पर बहुत जिम्मेदारियां सौंपी हैं इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टीएन शेषन की तरह के सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होने चाहिए। जहां तक यह सवाल है कि अदालत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर टिप्पणी क्यों की? तो हम आपको बता दें कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग की गयी है। कहा जा रहा है कि यदि इस कॉलेजियम प्रणाली में देश के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हों तो सरकार पर कुछ अंकुश लग सकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी एमपी में जुड़ेंगे राहुल से, शनिवार को इंदौर आएंगे

❑ इंदौर

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 26 नवंबर को इंदौर आएंगे। वे शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली से विमान से इंदौर आएंगे। संविधान दिवस के मौके पर वे महू जाकर डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी महू में पहुंचेगी। खरगे उसमें शामिल होकर गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हो जाएंगे।

खरगे महू में ड्रीमलैंड चौराहे पर होने वाली जनसभा में भी भाग लेंगे। इसके बाद वे इंदौर आकर रात्रि विश्राम करेंगे। 27 नवंबर को वे विशेष विमान से गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के लिए वडोदरा जाएंगे। वहां चुनावी सभाएं लेंगे। खरगे की मध्यप्रदेश यात्रा ऐसे समय होगी, जब 26 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचने वाली है। खरगे यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के साथ कुछ देर पैदल भी चलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे का यह पहला इंदौर दौरा है। विमानतल पर उनके स्वागत के इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद वे महू की सभा में इंदौर ग्रामीण के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। महू की सभा को सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो यात्रा का इंदौर का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राहुल 27 नवंबर को सुबह छह बजे महू से चलेंगे। दोपहर में राऊ में यात्रा रुकेगी। यहां लंच के बाद शाम चार बजे यात्रा शुरू होगी, जो राजेंद्र नगर ब्रिज से चाणक्य पुरी होकर चोइथराम मंडी की तरफ जाएगी। यहां से कलेक्टोरेट तिराहा होते हुए यात्रा राजवाड़ा पहुंचेगी।

अभिषेक बच्चन 27 नवंबर को सीहोर आएंगे तहसील परिसर में होना है फिल्म की शूटिंग

❑ सीहोर

सीहोर में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अब अभिषेक बच्चन यहां अपनी फिल्म की शूटिंग करने आ रहे हैं। सब ठीक रहा तो अभिषेक बच्चन 27 नवंबर को सीहोर पहुंचेंगे और तहसील परिसर में फिल्म की शूटिंग होगी। दक्षिण भारतीय एक फिल्म में अभिषेक बच्चन कास्ट किए गए हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े जीशान जाफरी ने बताया कि 27 नवंबर को अभिषेक बच्चन सीहोर आ रहे हैं, तहसील कार्यालय शूटिंग होना है। उनके आने को लेकर सभी अनुमतियों की औपचारिकता पूरी की जा रही हैं। अभिषेक बच्चन साउथ की मूवी केडी फिल्म के सीन के लिए सीहोर आ रहे हैं। फिल्म केडी के शूट मध्यप्रदेश के भोपाल, ओरछा और सीहोर में फिल्माए जा रहे हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग भोपाल के भोजपुर में चल रही है। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को फिल्म की शूटिंग सीहोर जिला मुख्यालय पर होगी। इसमें अभिषेक बच्चन अपना रोल प्ले करेंगे। दिसंबर में भी फ़िल्म की शूटिंग नगर में होगी, जिसमें पंचायत के कलाकार जीतू भी सीहोर आएंगे। पहले भी कई फिल्मों में दिखा है सीहोर दशकों पहले बुधनी के जंगलों में नया दौर की शूटिंग का सिलसिला अब भी जारी है। हाल के कुछ वर्षों में यहां टॉयलेट की शूटिंग हुई जिसमें अक्षय कुमार आए थे। जय गंगा जल की शूटिंग में प्रियंका चोपड़ा आई थीं। बुधनी में आश्रम की शूटिंग में बॉबी देवल बुधनी और सीहोर आए। ग्राम महोडिया में पंचायत वेब सीरीज की शूटिंग हुई।

हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर एसपी से शपथ पत्र में मांगा जबाब

याचिकाकर्ता का मोबाइल लेकर पुलिस ने बंद करवाई सीएम हेल्पलाइन की शिकायत

❑ जबलपुर

मध्यप्रदेश पुलिस वाकई में अजब है, नरसिंहपुर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसा कारनामा किया है कि जिसके बाद आज हर कोई यही कह रहा है। पुलिस ने एक शिकायतकर्ता का मोबाइल जब्त कर पुलिस के खिलाफ ही दर्ज सी.एम हेल्पलाइन शिकायत को बंद करवा दिया। जिसके बाद शिकायतकर्ता हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा।

मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस के इस कृत्य को गंभीर मानते हुए नरसिंहपुर एसपी को निर्देश दिए है की इस मामले में शपथ पत्र में जबाब पेश करें। नरसिंहपुर निवासी अभिषेक राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि मेरे द्वारा दिसम्बर 2021 में राधेश्याम राय, राकेश राय व राजेन्द्र उदेनिया के खिलाफ शिकायत कर आवास योजना में की गई गड़बड़ी उजागर की गयी थी, जिसमे प्रशासन द्वारा जांच की गई और बाद में फिर वसूली के आदेश भी जारी किए गए । इससे खफा होकर तीनों व्यक्तियों ने कोतवाली पुलिस से मिलकर याचिकाकर्ता के खिलाफ शराब के लिए अवैध वसूली एवं मारपीट के दो आपराधिक मामले कोतवाली थाने में दर्ज करवा दिए, जिसकी जानकारी याचिकाकर्ता को नही थी। 21 जून को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभिषेक राय को एक लंबित शिकायत में एफ.आई.आर दर्ज करने का आश्वासन देकर फोन कर बुलाया गया था, पीड़ित जैसे ही थाने पहुंचा तो उसके मामले में शिकायत दर्ज कर उसे एफ.आई.आर की कॉपी दी गई, किन्तु उसी दिन दोपहर साढ़े तीन बजे उसके खिलाफ दर्ज दो झूठे मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया।नरसिंहपुर कोतवाली पुलिस ने इस घटनाक्रम के दौरान उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर उसके माध्यम से सी.एम हेल्पलाइन 181 में फोन कर पुलिस के विरुद्ध लंबित एक शिकायत के निराकरण से सहमति व संतुष्टि व्यक्त करते हुए बंद करवा दिया। बाद में पुलिस ने आवेदक को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलते ही पुलिस द्वारा उसे मोबाइल वापस लौटाते हुए उससे मोबाइल प्राप्त करने की पावती ले ली गई और गिरफ्तारी प्रपत्र में मोबाइल लौटाने की बात का उल्लेख कर दिया गया। पर जब याचिकाकर्ता ने अपना मोबाइल देखा तो उसका संपूर्ण डाटा डिलीट कर दिया गया था जिसमें उसके लंबित मामलों के साक्ष्य, कॉल रिकार्डिंग, वीडियो आदि मौजूद थे।याचिकाकर्ता के कॉल स्टेटमेंट से गिरफ्तार रहने के समय सी.एम हेल्पलाइन में उसके फोन से ही फोन लगा कर बंद करने का खुलासा भी हुआ।

20 हजार से अधिक हुआ टैक्स तो मकान होगा कुर्क, 10 हजार मकान मालिक की सूची तैयार

❑ जबलपुर

राजस्व को बढ़ाने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम के द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। जिनका अभी 20 हजार से अधिक टैक्स बकाया है। राजस्व उपायुक्त पीएन सनखेरे के मुताबिक सभी 16 संभागों के करीब 9 हजार 982 मकान मालिकों को चिन्हित किया गया है। जिन्हें बकायदा कॉल, मैसेज के माध्यम से टैक्स जमा करने की हिदायत दी जा रही है। ऐसे ही करीब 10 हजार लोगों से 109 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल किया जाना है। यदि मकान मालिक टैक्स जमा नहीं करते हैं। तो मकान पुर करने की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि बकायादारो की बकाया राशि पर मार्च से लेकर दिसंबर तक 8त्न का अधिकार लगता है। वही जनवरी से 7त्न अधिभार और बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में बकाया राशि पर 15त्न अधिभार के साथ टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स वसूलने में सबसे अधिक बकाया 1 हजार 125 मकान मालिक संभाग क्रमांक 3 और सबसे कम संभाग क्रमांक 9 में 170 मकान मालिक है। जिनसे 20 हजार से अधिक टैक्स वसूल किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और जल शुल्क नहीं जमा करने वाले दो लाखों लोगों को भी बिल दिया जा रहा है। जिनसे 49 करोड़ रुपए वसूल किया जाना हैं।

निगम ने एक साल से नहीं किया ठेकेदारों को भुगतान

❑ छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा नगर निगम के ठेकेदारों ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर भुगतान में आ रही परेशानी को लेकर धरना दे दिया जिससे काफी देर तक गहमागहमी का माहौल देखा गया। वित्तीय भार से डगमगाती नैया को संभालने नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह द्वारा डूबने से बचाने प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में वे उन तमाम कार्यो पर कसावट ला रहे है जिससे निगम को संभाला जा सके। लेकिन इसमें उन्हें सहयोग की जगह विरोध का सामना करना पड़रहा है। विरोध का शंखनाद निगम के ठेकेदारों द्वारा किया गया। एक जुट हुए ठेकेदार कमिश्नर के कक्ष के करीब नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि शहर में नए कामों की शुरूआत करने से पहले ठेकेदारों को पुराने कामों का बकाया भुगतान किया जाए। इसके बाद भी नए निर्माण कार्यों की शुरुआत की जाए। रुके हुए भुगतान की मांग ठेकेदारों की सही है लेकिन अपनी बात रखने के लिए अपनाया गया तरीका गलत है। नगर निगम आयुक्त ने भी कक्ष में बुलाने के बाद ठेकेदारों को यही समझाईश दी। उनका कहना था कि राजस्व बढ़ाने के प्रयासों के अलावा कर्मियों से लेकर ठेकेदारों के भुगतान को लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है।

दमोह के 17 मजदूरों को कोल्हापुर में बनाया बंधक, जिला प्रशासन ने छुड़वाया

❑ दमोह

दमोह से महाराष्ट्र गए मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। उन्होंने दमोह जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद 17 मजदूरों को जिला प्रशासन की मदद से गुरुवार को सकुशल दमोह पहुंचाया गया है। दमोह जिला प्रशासन द्वारा इन मजदूरों को बंधक मुक्त किए जाने के प्रयास किए गए थे।

दमोह पहुंचे मजदूरों में अरविंद अहिरवाल ने बताया कि वह दस नवंबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के सांगली तहसील के गढ़वाली गांव गए थे। यहां पर ठेकेदार द्वारा सभी मजदूरों से काम लिया गया, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की रुकने या खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई और मजदूरी भी कम दी जा रही थी। इसके अलावा ठेकेदार से मजदूरी मांगने पर उसने मारपीट की और धमकी भी दी गई। जिस कारण से सभी मजदूर घबरा गए थे। इस बात की जानकारी इन मजदूरों ने अपने परिजनों को दी। परिजनों ने दमोह जिला प्रशासन को अवगत कराया।

कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने वहां के जिला प्रशासन से संपर्क किया और संबंधित थाना प्रभारी से मजदूरों को वहां से बंधक मुक्त कराने के लिए कहा। सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा इन सभी मजदूरों को वहां से बंधन मुक्त कराया। वहां से दमोह के लिए रवाना कराया। इन मजदूरों ने बताया कि बंधन मुक्त होने के बाद वह ट्रेन के माध्यम से दमोह के लिए रवाना हुए थे जो कि सकुशल गुरुवार को दमोह आ गए। इन मजदूरों ने यह भी बताया कि उन्हें पहचान के गोलू ठाकुर एवं विक्रम दोनों गन्ने की कटाई के लिए साथ लेकर गए थे।

परिवहन विभाग ने आरटीओ ने नियमों के तहत वाहन संचालित करने के दिए निर्देश

❑सिवनी मालवा

सिवनी मालवा में परिवहन विभाग ने गुरुवार को स्कूली वाहनों की जांच का अभियान चलाया। इस दौरान जीवा ज्योति हायर सेकेंडरी, सहित नगर में संचालित अन्य स्कूलों के बसों की जांच की गई। कमी मिलने पर जीवा ज्योति स्कूल की बस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। स्कूलों में प्रबंधन को हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई गाइड लाइन के अनुसार बसों के संचालन के निर्देश दिए गए है। आरटीओ निशा चौहान ने बताया कि स्कूली बसों में कैमरा, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बाक्स, स्पीड गवर्नर, जाली, बैग रखने की उचित जगह होनी चाहिए। कुछ अन्य मापदंड भी हाई कोर्ट ने तय किए हैं। अभियान चलाकर बसों की जांच की जा रही है। अन्य स्कूली वाहनों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। आज कई बसों की जांच की गई है, ऐसे ही आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आरटीओ निशा चौहान ने स्वयं बसों में जाकर स्कूली बच्चों से भी चर्चा की व उनसे जानकारी ली कि बसों में उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं होती है। साथ ही उन्होंने बस चालकों को भी समझाइश दी है कि बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। यदि आगे भी जांच में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल बस में इस तरह ओवरलोड बच्चें बैठा रहे 32 की क्षमता वाली बस में 50 बच्चें, स्टूडेंट्स बोले, एक सीट पर बैठते है तीन बच्चें

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के सिवनी-मालवा में जीवा ज्योति पब्लिक स्कूल द्वारा नियमों को ताक में रखकर स्कूल बस को संचालित हो रही है। एक सीट पर तीन-चार बच्चें को बैठाकर परिवहन किया जा रहा। जिससे बच्चों को बैठने में परेशानी के साथ, उनकी जान को भी खतरें में जा रहा। ओवरलोडिंग स्टूडेंट्स बैठाने की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन पर 10 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई हुई। परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने गुरुवार सुबह 7 बजे स्टाफ के साथ जाकर जीवा ज्योति बसों की चैकिंग की। आरटीओ चौहान ने बस में बैठे स्टूडेंट्स से जानकारी। स्टूडेंट्स ने कहा कि एक सीट पर दो की जगह तीन-चार बच्चें को बैठाया जाता है। बड़े बच्चों को कभी कभी खड़े होकर आना-जाना पड़ता। हमने प्राचार्य से शिकायत की। लेकिन प्राचार्य ने हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। ओवरलोडिंग स्टूडेंट्स बैठाने का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार सुबह 7 बजे आरटीओ निशा चौहान स्टॉफ के साथ सिवनी मालवा पहुंची।

ऑस्ट्रेलिया से हारकर इंग्लैंड वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, भारत के पास टॉप पर पहुंचने का मौका

एजेंसी ❑नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। इस सीरीज में हार के बाद इंग्लैंड की टीम वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गई है। इसका फायदा न्यूजीलैंड को मिला है और कीवी टीम वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत के पास भी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने का मौका बन गया है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जीत हासिल कर पहला स्थान हासिल कर सकती है।

वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने के लिए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों मैच जीतने होंगे। दो मैच जीतने पर भारत और इंग्लैंड के अंक बराबर होंगे, लेकिन रेटिंग प्वाइंट की गणना में भारतीय टीम पीछे रह जाएगी और दूसरे स्थान पर रहेगी। भारत अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत जाता है तो भारत और इंग्लैंड के

पास 113 अंक होंगे। इस स्थिति में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रहेगी। वहीं, तीनों मैच जीतने पर भारत 116 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले, इंग्लैंड 119 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर था।

इंग्लैंड की टीम दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड से पांच अंक आगेथी। हालांकि, लगातार तीन हार के परिणामस्वरूप उन्हें छह अंक गंवाने पड़े। सीरीज खत्म होने के बाद इंग्लैंड के पास 113 अंक हैं, जबकि न्यूजीलैंड के पास 114 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया के शानदार प्रदर्शन का इनाम भी मिला। यह टीम एक स्थान की छलांग के साथ 112 रेटिंग अंक हासिल कर चुकी है और रैंकिंग में फिलहाल चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हटाकर चौथा स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के पास 107 अंक हैं। वहीं, भारत 112 रेटिंग अंक और कुल मिलाकर 3802 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 112 अंक और 3572 रेटिंड अंक के साथ चौथे नंबर पर है।

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जडेजा

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा अगले महीने बांग्लादेश दौरे से बाहर हो सकते हैं। एशिया कप के दौरान चोटिल होने वाले जडेजा अब तक पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे और दो टेस्ट मैच की सीरीज में उनका नाम भारतीय टीम में शामिल हैं, लेकिन जल्द ही उनकी जगह शाहबाज अहमद का नाम भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जडेजा अभी तक अपनी चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। वह अगले महीने 34 साल के हो रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी मैच एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ खेला था। इसके बाद एशिया कप के अहम मैचों में और पूरे टी20 विश्व कप में नहीं खेल पाए थे। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम का एलान करते हुए, बीसीसीआई ने कहा था कि जडेजा फिट होने पर ही इस दौरे में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। भारतीय चयन समिति इस सप्ताह के अंत में जडेजा की जगह किसी खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल कर सकती है। इसी दौरान इंडिया ए टीम का एलान होने की भी संभावना है। भारतीय चयन समिति को हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि, इसके अधिकतर सदस्य विजय हजारे ट्रॉफी के मैच देख रहे होंगे। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इंडिया ए टीम में मौका मिल सकता है।

स्पेन ने कोस्टा रिका को 7-0 से हराया

एजेंसी ❑दोहा

फीफा विश्व कप 2022 में स्पेन की टीम ने शानदार शुरुआत की है। पहले मैच में स्पेन ने कोस्टा रिका को 7-0 के बड़े अंतर से हराया। इस बड़ी जीत के साथ ही स्पेन के लिए प्री-क्वार्टर फाइनल की राह आसान हो गई है। जीत के बाद स्पेन के मुख्य कोच लुइस एनरिक ने कहा कि उनकी टीम गेंद को संभालने और फिनिशिंग में असाधारण थी। टीम उसी अंदाज में खेली, जैसे कई साल से खेलती नजर आ रही है। वहीं, कोस्टा रिका के कोच सुआरेज ने कहा कि उनकी टीम का अटैक बैगद कमजोर था। इसी वजह से वह स्पेन के कोई चुनौती नहीं दे सके।

स्पेन के मुख्य कोच लुइस एनरिक ने कहा जब चीजें इस तरह से चलती हैं, तो फुटबॉल एक अद्भुत खेल बन जाता है। हम गेंद को संभालने और फिनिशिंग में असाधारण थे। हम दबाव में असाधारण थे और जिन 17 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, वे बहुत अच्छे थे। यह राष्ट्रीय टीम है जो सभी चैंपियनशिप में सबसे अधिक गोल करती है। हमारे पास एक बेंचमार्क खिलाड़ी नहीं हो सकता है जो 30 गोल करता है लेकिन हमारे पास फेरान, डैनी ओल्मो, मार्को असेंसियो, गेवी जैसे खिलाड़ी हैं और मैंने कभी भी गोल की चिंता नहीं की। कोस्टा रिका के मुख्य कोच लुइस फर्नांडो सुआरेज ने कहा कि उनकी टीम गेंद पर नियंत्रण नहीं पा सकी। इसी वजह से यह टीम अटैक नहीं कर पाई। सुआरेज ने कहा, हमें गेंद नहीं मिली और हमारी ओर से आक्रमण में कुछ नहीं था। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि हम बुरे थे और जो हुआ उसकी जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी। हम चिंतित हैं कि टीम इससे बाहर नहीं निकल पाएगा या नहीं। मुझे उम्मीद है कि हम चीजों को सुलझा सकते हैं और जापान के खिलाफ मैच के लिए पहले काम करना शुरू कर सकते हैं।

श्रीलंकाई खिलाड़ी चमिका करुणारत्ने पर लगा एक साल का बैन, चार लाख का जुर्माना

एजेंसी ❑कोलंबो

श्रीलंका के ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने पर एक साल का बैन लगाया है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग चार लाख रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है। चमिका करुणारत्ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उनके ऊपर अनुशासन तोड़ने के आरोप लगे थे। इसके बाद तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति ने करुणारत्ने को दोषी पाया। इसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। करुणारत्ने ने अनुशासन से जुड़े कई नियम तोड़े हैं। जांच में उनके ऊपर लगाए गए सभी दोष सही पाए गए हैं। इस मामले पर बयान जारी करते हुए श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया करुणारत्ने ने जिन नियमों का उल्लंघन किया है। उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की कार्यकारी समिति से उन्हें कड़ी चेतावनी देने और एक ऐसी सजा देने की सिफारिश की है जिसका उनके करियर पर ज्यादा प्रभाव न पड़े। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने से बचें। जांच पैनल की रिपोर्ट और सिफारिशों

के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की कार्यकारी समिति ने करुणारत्ने के क्रिकेट के सभी रूपों में भाग लेने से एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है, और उन्हें एक साल की अवधि के लिए निलंबित किया जाएगा। करुणारत्ने ने ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप में सात मैचों में तीन विकेट लिए। साथ ही बल्लेबाजी का मौका मिलने पर भी प्रभावित किया था।

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के बांग्लादेश की टीम का एलान

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ अगले महीने तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। तमीम इकबाल वनडे सीरीज में बांग्लादेश की टीम की कमान संभालेंगे। वहीं, वनडे टीम में दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की वापसी हुई है। वह इस साल जुलाई-अगस्त से वनडे मैच नहीं खेल रहे थे। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए चुनी गई टीम में मोसद्दक हुसैन, शोरिफुल इस्लाम और ताइजुल इस्लाम को नहीं चुना गया है। टी20 में खराब फॉर्म की वजह से मोसद्दक को वनडे टीम में जगह नहीं दी गई है। हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में 26 साल के मोसद्दक ने पांच मैचों में 38 रन बनाए थे। उनका औसत 9.50 का रहा था। तेज गेंदबाज इबादत हुसैन, जिन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया था, उन्हें स्क्वॉड में बरकरार रखा गया है।

सूर्यकुमार ने टी20 रैंकिंग में हासिल किए 895 अंक, मोहम्मद रिजवान से 54 प्वाइंट आगे

एजेंसी ❑दुबई

आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की बादशाहत कायम है। वह आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भी पहले स्थान पर बने हुए हैं। टी20 विश्व कप में 239 रन बनाने वाले सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सबसे ज्यादा 124 रन बनाए और सिर्फ एक बार आउट हुए। दूसरे मैच में उन्होंने नाबाद 111 रन बनाए और अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 895 अंक हासिल कर लिए थे। हालांकि, अगले मैच में वह 13 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और उन्हें पांच अंक का नुकसान हुआ। फिलहाल सूर्यकुमार यादव 890 अंकों के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। वह दूसरे स्थान पर मौजूद मोहम्मद रिजवान से 54 अंक आगे हैं, जिनके पासस 836 रेटिंग प्वाइंट हैं। न्यूजीलैंड के डेवोन कॉन्वे ने दूसरे मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी और बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए वह तीसरे स्थान पर आ गए हैं। कॉन्वे के पास 788 अंक हैं। वहीं, चौथे स्थान पर मौजूद बाबर के पास 778 अंक हैं। भारत के ईशान किशन को भी अच्छी बल्लेबाजी का फायदा मिला है और 10 पायदान के सुधार के साथ वह 33वें स्थान पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन को भी एक पायदान का फायदा हुआ है और वह सातवें स्थान पर आ गए हैं, जबकि ग्लेन फिलिप्स

पांच स्थान के सुधार के साथ 35वें स्थान पर हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन भारत के भुवनेश्वर कुमार दो स्थान के फायदे के साथ 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के टिम साउदी को भी दो स्थान का फायदा हुआ है और वह 14वें स्थान पर आ गए हैं। साउदी ने इस सीरीज के दूसरे मैच में हैट्रिक ली थी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों को आईसीसी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वॉर्नर एक स्थान ऊपर पांचवें पायदान पर आ गए हैं। वहीं, स्टीव स्मिथ को तीन स्थान का फायदा हुआ है और वह सातवें स्थान पर आ गए हैं। वहीं, सीरीज में 240 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड 12 स्थान के फायदे के साथ 30वें स्थान पर आ गए हैं। गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क को चार पायदान का फायदा हुआ है और वह चौथे स्थान पर आ गए हैं। वहीं, स्पिन गेंदबाज एडम जंपा ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर ली है। वह 655 अंक के साथ सातवें स्थान पर आ गए हैं। इस सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा 11 विकेट लिए थे और उन्हें आठ स्थान का फायदा हुआ है।

कुल एफडीआई प्रवाह भी चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 39 अरब डॉलर रह गया

एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 14 फीसदी गिरावट

कर्ज वृद्धि के लिए बैंकिंग सिस्टम हो बेहतर

एजेंसी ❑ नई दिल्ली/कैनबरा

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी प्रवाह चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि में 14 फीसदी घटकर 26.9 अरब डॉलर रहा। डीपीआईआईटी के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 31.15 अरब डॉलर था। कुल एफडीआई प्रवाह भी चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 39 अरब डॉलर रह गया।?

बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों से ओपीडी और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टरों या अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का नेटवर्क बनाने के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) का लाभ उठाने को कहा है। एचपीआर के तहत केवाईसी या आधार का उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं के पेशेवरों की आईडी बनाई जाती है। इसमें मेडिकल योग्यता भी शामिल होती है। भारतीय बीमा एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने एचपीआर को शामिल किया है। यह पूरे भारत में आधुनिक और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले पेशेवरों के पंजीकृत और सत्यापित डॉक्टरों का एक भंडार है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने वाली सामान्य और हेल्थ बीमा कंपनियां भी ओपीडी या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रजिस्ट्री का लाभ उठाने पर विचार कर सकती हैं।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली ऊंची कर्ज वृद्धि को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने बुधवार को कहा, पिछली बार की कर्ज वृद्धि से सबक लेते हुए इस बार इसकी पहले से तैयारी की गई है। उन्होंने कहा, इस समय टिकाऊ विकास देखने को मिल रहा है।?बैंकिंग प्रणाली ने कई वर्षों तक वार्षिक कर्ज वृद्धि को दो अंकों में ले जाने के लिए संघर्ष किया था। अब यह काफी उच्च स्तर पर है। खारा ने कहा कि कई सारे बदलाव हैं, जिनसे बैंकों को मदद मिली है। इसमें दिवालिया कोड, जीएसटी नेटवर्क डाटा, रेटिंग इकोसिस्टम और क्रेडिट ब्यूरो जैसे कारक हैं। उन्होंने कहा, 2047 तक जीडीपी को 40 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाना बड़ा कार्य है। किसी के बैंक खाते में न्यूनतम जमा से कम रकम है तो इस पर कितना जुर्माना लगाना है यह संबंधित बैंक ही तय करेगा। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि बैंक के पास बोर्ड होता है और वह खुद एक स्वतंत्र बॉडी है। इस पर सरकार कोई फैसला नहीं करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जनधन योजना को बढ़ाने के लिए बैंकों को विशेष अभियान आयोजित करने को कहा है। देश में एक लाख आबादी पर 49,135 जनधन खाते हैं।

जम्मू कश्मीर में यह 21,252 है। सेबी ने कहा कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से पांच दिन तक पीएसीएल निवेशकों के रिफंड की प्रक्रिया बंद रहेगी। फिलहाल इस पोर्टल पर गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा है। यह पोर्टल 31 जनवरी, 2023 तक चालू रहेगा। पीएसीएल ने निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपये जुटाई थी। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत 24 नवंबर यानी बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे।?एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।?जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के छह देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान व बहरीन का संघ है।

अमेरिका और पश्चिमी देश रूसी तेल पर लगाएंगे प्राइस कैप, जल्द हो सकती है घोषणा

एजेंसी ■ नई दिल्ली

फरवरी 2022 से जारी रूस और युक्रेन जंग के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस बीच रूस भारत को सस्ती दरों पर पेट्रोलियम पदार्थ उपलब करा रहा है। अब भारत पर तेल बेच रहे रूस पर नकेल कसने की मंशा से अमेरिका और उसके सहयोगी देश तेल की कीमतों 65 डॉलर से 70 डॉलर प्रति बैरल का कैप लगाने की योजना बना रहे हैं। सस्ते दामों पर भारत को तेल बेच रहे रूस पर नकेल कसने के लिए जी-7 समूह और यूरोपीय यूनियन जल्द की प्राइस कैप का एलान कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर भारत के रूस से तेल खरीदने पर पड़ सकता है। रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने की मंजूरी के लिए यूरोपीय यूनियन में शामिल सभी देशों के राजदूतों ने बुधवार को बैठक की और इसमें प्राइस कैप लेवल का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को जैसे ही मंजूरी मिलेगी, प्राइस कैप की घोषणा हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। भारत को रूस से तेल की खरीदारी पर छूट मिल रही है। अमेरिका व पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत और रूस के बीच तेल की लेन-देन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया जाता है तो उससे भारत भी प्रभावित होगा।

बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनी में टाटा ग्रुप खरीदेगी हिस्सेदारी

TATA
WE'RE ALL GOING THE DISTANCE.

एजेंसी ❑ नई दिल्ली

टाटा ग्रुप अब बोतलबंद पीने का पानी बेचने वाले सबसे ब्रांड बिसलेरी इंटरनेशनल में हिस्सेदारी खरीदने का प्लान बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा ग्रुप ने भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी जिसका स्वामित्व रमेश चौहान के पास है, उन्हें बिसलेरी इंटरनेशनल में हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा समूह पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कारोबार के प्रति उत्साह दिखा रहा है और उसने बिसलेरी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी को प्रस्ताव दिया है। टाटा यह कदम एंट्री लेवल, मिड-सेगमेंट और प्रीमियम पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर कैटेगरी में पैर जमाने के लिए उठा रही है। उम्मीद है कि इस फैसले से कंपनी को ऐसा करने में मदद मिलेगी। इस कारोबार में एंट्री करने से टाटा का रिटेल स्टोर्स, केमिस्ट चैनल्स, इंस्टीच्यूशनल चैनल्स, होटल्स और रेडी-टू-गो मार्केट नेटवर्क बढ़ेगा। बता दें कि रेस्तरां और एयरपोर्ट के अलावा बल्क वाटर डिलिवरी में भी बिजनेस में भी बिसलेरी मिनरल वाटर लीडिंग ब्रांड है। बता दें कि टाटा ग्रुप का कंज्यूमर कारोबार काफी बड़ा बड़ा।

यह कंपनी स्टारबक्स कैफे का संचालन करती है। इसके अलावे कंपनी के पास टेटली चाय, आठ बजे कॉफी, सोलफल अनाज, नमक, दालों से जुड़े ब्रांड हैं। वहीं बोतल बंद पानी के व्यवसाय में भी न्यूरिशको ब्रांड के तहत टाटा ग्रुप का दखल है। अब ग्रुप बिसलेरी का अधिग्रहण कर बोतलबंद पानी के अपने कारोबार को नया विस्तार देना चाहती है।

तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। देश में तेल के दाम लगभग पिछले चार महीने से ज्यादा समय से स्थिर हैं। आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको ऋस्कऔर अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं।

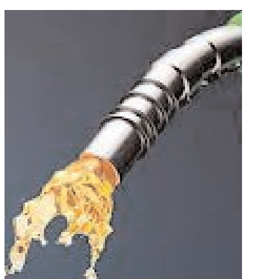

पेंशन योजना में बदलाव की तैयारी, सेवानिवृत्ति पर मिलेगा ज्यादा पैसा

एजेंसी, नई दिल्ली। सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना की वेतन सीमा बढ़ा सकती है। इससे कर्मचारियों और कंपनियों के अनिवार्य योगदान में वृद्धि होगी। साथ ही, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले फंड के लिए ज्यादा बचत में मदद मिलेगी। अभी ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति महीने है। इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो 75 लाख और कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। अभी इनकी संख्या 6.8 करोड़ है।

किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर अनुदान की घोषणा, आरबीआई ने दी मंजूरी

एजेंसी ■ नईदिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए संशोधन के साथ ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। आरबीआई बुधवार को एक बयान में कहा कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 3,00,000 रुपये तक के अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज दर सात प्रतिशत होगी। चालू वित्त वर्ष 2022-23 और अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज अनुदान 1.5 प्रतिशत होगा। खेती और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये की कुल सीमा तक अल्पावधि फसल ऋण और अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज अनुदान प्रदान किया जाए इस उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक (स्न्नक्क) और कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ तहत कर दिया गया है। आरबीआई के अनुसार ब्याज में छूट की गणना ऋण राशि पर संवितरण/निकासी की तारीख से किसानों की ओर से ऋण की वास्तविक चुकौती की तारीख तक या बैंकों की ओर से निर्धारित ऋण की देय तिथि तक, जो भी पहले हो पर की जाएगी। यह छूट एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए होगी। विशेष रूप से, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। ब्याज पर अनुदान आमतौर पर कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित करता है और साथ ही वित्तीय स्वास्थ्य और ऋण देने वाली संस्थाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित करता है।

स्वत्वाधिकारी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड,तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। संपादक :- नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)